जलवायु नीति, सार्वजनिक नीति और एसडीजी के स्थानीयकरण पर केंद्रित रहा विमर्श

पटना (आससे)। चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट पटना द्वारा आयोजित दो दिवसीय तृतीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन [illegible]2025 के दूसरे और अंतिम दिन का समापन आज सार्वजनिक नीति, जलवायु परिवर्तन और सतत विकास लक्ष्यों (स्थ्लह्य) के स्थानीयकरण पर केंद्रित गहन संवादों और प्रस्तुतियों के साथ हुआ। दूसरे दिन की शुरुआत दो तकनीकी सत्रों से हुई। पहले सत्र में जलवायु परिवर्तन और स्थिरता को लेकर कृषि, उद्योग, श्रम प्रवासन और खाद्य सुरक्षा जैसे विविध विषयों पर शोध प्रस्तुत किए गए। शोधकर्ताओं ने यह रेखांकित किया कि किस प्रकार जलवायु नीतियों को भारत के सतत विकास एजेंडा से जोड़ा जा सकता है। दूसरे तकनीकी सत्र में सार्वजनिक नीतियों के विभिन्न क्षेत्रों—शिक्षा, आधारभूत संरचना, महिला सशक्तिकरण, हरित तकनीक, और डिजिटल सुरक्षा—पर प्रभाव का विश्लेषण किया गया। वक्ताओं ने नीति निर्माण में साक्ष्य आधारित दृष्टिकोण और क्षेत्रीय प्रभाव आंकलन की आवश्यकता पर जोर दिया। दोपहर के सत्र में 'एसडीजी का स्थानीयकरण- क्षेत्रीय अनुभवों से प्राप्त साक्ष्य' विषय पर एक उच्चस्तरीय पैनल चर्चा आयोजित की गई। इस चर्चा में भारत के विभिन्न राज्यों, विशेषकर बिहार में स्थ्लह्य को स्थानीय नीतियों में लागू करने के अनुभव साझा किए गए। चर्चा का संचालन डॉ. सुधांशु कुमार (बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी) ने किया और इसमें शिक्षाविदों, पंचायती राज प्रतिनिधियों, आशा कार्यकर्ताओं, और नागरिक समाज के सदस्यों की सक्रिय भागीदारी रही। सम्मेलन के समापन सत्र में अन्ना विश्वविद्यालय, चेन्नई के प्रो. डॉ. एस. गणपति वेंकटासुब्रमणियन ने पर्यावरणीय शासन और कानूनी ढांचे की भूमिका पर विचार रखे। उन्होंने सतत विकास में नीति और कानून की सामूहिक भूमिका को रेखांकित किया। सीआईएमपी के एसोसिएट प्रोफेसर प्रो. सिबानंद सेनापति ने दो दिवसीय सम्मेलन की प्रमुख उपलब्धियों का सारांश प्रस्तुत किया, जबकि निदेशक प्रो. (डॉ.) राणा सिंह ने सभी प्रतिभागियों को धन्यवाद ज्ञापित किया और आयोजन टीम की सराहना की। सम्मेलन का औपचारिक समापन प्रो. देबब्रत समंता (सम्मेलन संयोजक) के धन्यवाद भाषण एवं राष्ट्रगान के साथ हुआ।

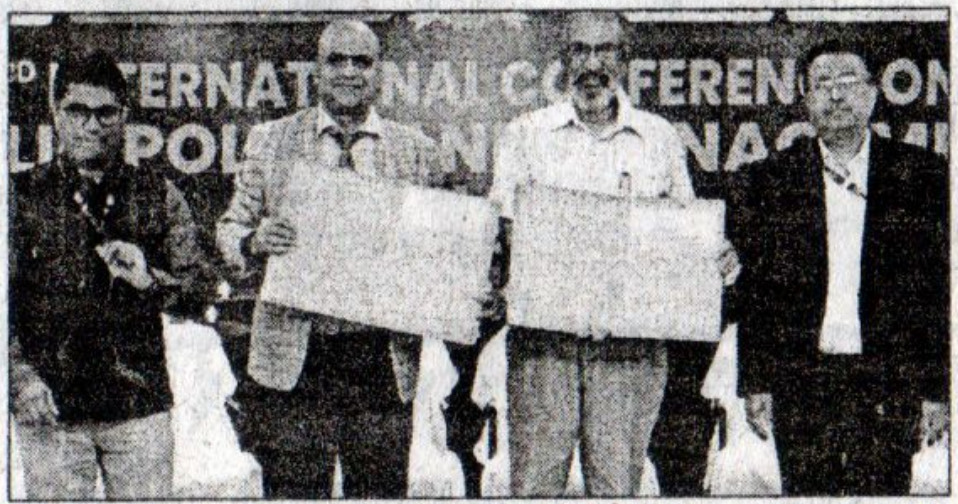

Aaj 1 Page No - 08 ! Date - 27-06-2025 !

सीआइएमपी में पर्यावरणीय जोखिम पर हुई चर्चा

पटना. चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट पटना की ओर से आयोजित तृतीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन (आइसीपीपीएम-2025) के अंतिम दिन नीति-निर्माताओं, शोधकर्ताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने जलवायु लचीलापन, सतत विकास और स्थानीय शासन पर विचार साझा किए. उद्योग व कृषि में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव, पर्यावरणीय जोखिम, ग्रामीण आजीविका, श्रमिक प्रवासन और खाद्य सुरक्षा जैसे विषयों पर शोध प्रस्तुत हुए. दूसरे सत्र में शिक्षा सुधार, डिजिटल सुरक्षा, असंगठित क्षेत्र की महिलाएं, आधारभूत ढांचा और हरित गतिशीलता पर नीति विश्लेषण हुआ. डॉ सुधांशु कुमार ने परिचर्चा का संचालन किया. प्रो एस गणपति वेंकटासुब्रमणियन ने सतत विकास में कानूनी ढांचे की भूमिका पर विचार रखे. सम्मेलन का समापन प्रो सिबानंद सेनापति द्वारा प्रस्तुत सारांश से हुआ. सीआइएमपी के निदेशक प्रो राणा सिंह ने प्रतिभागियों को सम्मानित किया और प्रो देबब्रत समंता ने धन्यवाद ज्ञापन दिया.

Prabhat Khabar ! Page No - 09 ! Date - 27-06-2025 !

सीआईएमपी • अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन और सतत विकास पर चर्चा

खाद्य सुरक्षा समेत कई मुद्दों पर शोध पत्र प्रस्तुत किए

एजुकेशन रिपोर्टर | पटना

चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट पटना (सीआईएमपी) में चल रहे अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आईसीपीपीएम 2025 का दूसरा और अंतिम दिन जलवायु परिवर्तन, सतत विकास और सार्वजनिक नीति जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर केंद्रित रहा। देश-विदेश के नीति-निर्माता, शोधकर्ता और सामाजिक कार्यकर्ता इसमें शामिल हुए। दिन की शुरुआत दो तकनीकी सत्रों से हुई। पहले सत्र में जलवायु परिवर्तन का कृषि और उद्योग क्षेत्र पर असर, पर्यावरणीय जोखिम, ग्रामीण आजीविका, श्रमिक प्रवासन और खाद्य सुरक्षा जैसे मुद्दों पर शोध प्रस्तुत किए गए। इन अध्ययनों में यह बताया गया कि कैसे जलवायु और स्थिरता से जुड़े प्रयासों को भारत के विकास लक्ष्यों में जोड़ा जा सकता है। सीआईएमपी के निदेशक प्रो. राणा सिंह ने कहा कि यह दो दिवसीय सम्मेलन सतत विकास और बेहतर नीति निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। दूसरे सत्र में शिक्षा, बुनियादी ढांचे, महिलाओं की भागीदारी, जलवायु अनुकूल कृषि, डिजिटल सुरक्षा और हरित यातायात जैसे विषयों पर चर्चा हुई। वक्ताओं ने कहा कि नीति बनाने के लिए सटीक आंकड़े और मजबूत मूल्यांकन प्रणाली जरूरी हैं। एसडीजी का स्थानीयकरण विषय पर एक खास पैनल चर्चा हुई, जिसमें यह बताया गया कि वैश्विक लक्ष्यों को स्थानीय स्तर पर कैसे लागू किया जाए। पैनल में बिहार और अन्य राज्यों के अनुभवों को साझा किया गया और बताया गया कि पंचायती राज संस्थाएं, आशा कार्यकर्ता और मजबूत संस्थागत ढांचा इस दिशा में कैसे मदद कर सकते हैं। इस सत्र का संचालन डॉ. सुधांशु कुमार ने किया। समापन अन्ना विश्वविद्यालय, चेन्नई के डॉ. एस. गणपति वेंकटासुब्रमणियन के संबोधन से हुआ, जिसमें उन्होंने कानून और पर्यावरणीय शासन की भूमिका को रेखांकित किया।

Dainik Bhaskar ! Page No - 06 ! Date - 27-06-2025 !